POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2021/अंक 04

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 अप्रेल, 2021 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट रखा। बजट में करीब-करीब सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

बजट में स्वास्थ सुविधाओं का विस्तार करने, किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा क्षेत्र को ज्यादा तवज्जह देने, औद्योगिक ढांचे को विकसित करने, बुनियादी ढांचे का विकास करने, सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने और खाद्य वस्तुओं में मिलावट पर सख्त सजा का प्रावधान करने जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सभी वर्गों की झोली खुशियों से भरने का प्रयास किया गया है।

मेरा मानना रहा है, बढ़ते कर्ज के बावजूद नियोजित रूप से खर्च करने की अक्षमता अच्छा संकेत नहीं होता। मुख्यमंत्री को प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई कदम उठाने होंगे। महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि सभी बजट घोषणाएं समय पर क्रियान्वित हों।

हालांकि मुख्यमंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष में राजस्व बढ़ाने और बजट घाटे को कम कर वित्तीय अनुशासन अपनाने की बात कही है। इसके लिए उन्हें प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ नौकरशाही को अधिक सक्रिय बनाना होगा। जितना वित्तीय संसाधनों को समय पर जुटाना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि उन्हें दक्षता के साथ खर्च किया जाए। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

हर बार की तरह, 'ग्राम गदर' में गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर पैनी नजर रखकर लाभान्वित हो सकें।

मिली नसीयतः प्रदेश में स्वास्थ सुविधाओं का होगा विस्तार

कोरोना महामारी के दौरान सामने आई चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने बजट में हर परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। बजट में 10 हजार 171 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को आगे लाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही राइट टू हेल्थ बिल भी लाया जाएगा। पहली बार यूनिवर्सल हेल्थ बीमा लागू किया जाएगा। इसके तहत हर परिवार को 850 रुपए में पांच लाख रुपए का चिकित्सा बीमा मिलेगा।

सात संभागीय मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज और 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ेगा। जयपुर के गणगौरी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बड़े शहरों में नए चिकित्सा संस्थान खोले जाएंगे। जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कई सुविधाओं के विस्तार पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनेगा।

बजट किसानों पर केन्द्रितः आय बढ़ाने के होंगे प्रयास

मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष से अलग से कृषि बजट की शुरुआत करने की घोषणा करते हुए बजट में कृषक एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है। बजट में 16 हजार करोड़ रुपए के ब्याजमुक्त फसली ऋण वितरित करने का प्रावधान है। इसमें मत्स्यपालकों व पशुपालकों को भी शामिल किया जाएगा। एक लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर देने की भी घोषणा की गई है। एक लाख किसानों के लिए कंपोस्ट की व्यवस्था की जाएगी। तीन वर्ष में 4 लाख 30 हजार हैक्टेयर भूमि सूक्ष्म सिंचाई के तहत विकसित होगी।

राजीव गांधी सेवा केंद्रों में किसान सेवा केंद्र खोले जाएंगे। मण्डियों को ऑनलाइन करने के लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में घोषित जीरो बजट नेचर फार्मिंग योजना के तहत तीन साल में 60 करोड़ रुपए खर्च कर 15 जिलों में 36 हजार किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

बजट में 50 हजार किसानों को सोलर पंप, 50 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन देने एवं जोबनेर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना, हनुमानगढ़ में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने की भी घोषणा की गई है। बजट में नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाए जाने की घोषणा भी है। बिजली के 13 लाख कृषि उपभोक्ताओं को अब 12 हजार रुपए सालाना सब्सिडी मिलेगी। 48 करोड़ रुपए की लागत से घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू होगी।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आयोजित परिचर्चा

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के साथ ही जैविक खेती के प्रचार प्रसार पर दिया जोर

''प्लास्टिक हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है, जिसके नकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खेती में बढ़ते रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मानव जीवन संकट में है। इनके बढ़ते गंभीर दुष्परिणामों से निपटने के लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे।''

'कट्स' द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एवं 'प्रो-ओर्गेनिक' परियोजना के तहत आयोजित वार्षिक राज्य स्तरीय परिचर्चा में यह उभरकर सामने आया। परिचर्चा के प्रारंभ में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 15 मार्च का दिन अब सम्पूर्ण विश्व में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने एवं उपभोक्ता आंदोलन को संगठित करने का वार्षिक उत्सव बन चुका है।

'कटस' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने अपने उद्बोधन में विभिन्न आंकड़ें प्रस्तुत करते हुए बताया कि किस तरह प्लास्टिक के उपयोग से सम्पूर्ण विश्व के पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कार्यक्रम में राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर के निदेशक डॉ. ए.एस. बलोदा ने परम्परागत कृषि विकास परियोजना के तहत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने और हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए सामूहिक रूप से जैविक खेती की मुहिम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

पदमश्री पुरस्कार प्राप्त किसान जगदीश पारीक ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि किस प्रकार जैविक खेती से किसान काफी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने बताया अब जैविक वस्तुओं की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कार्यक्रम के दौरान 'कट्स' के राजदीप पारीक ने 'प्रो-ओर्गेनिक' परियोजना के तहत की गई विभिन्न गतिविधियों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया। कार्यक्रम में कृषि अनुसंधान अधिकारियों, विशेषज्ञों, किसानों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित 60 से अधिक भागीदारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

शिक्षा को दी विशेष अहमियत

प्रदेश के बजट में इस वर्ष शिक्षा के लिए 13 हजार 309 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण स्कूलों के बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बजट में बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।

इस कार्यक्रम के तहत सभी राजकीय स्कूलों के कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को मुफ्त स्कूल ड्रेस दी जाएगी एवं कक्षा छह से आठ तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी दी जाएगी। इस पर करीब 470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दो साल में 1200 राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे।

37 हजार 400 आंगनबाड़ी केंद्रों व 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षा के लिए चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में 50 नए सरकारी स्कूल खोलने, 100 स्कूलों को क्रमोन्नत करने, 3500 स्कूलों में आधारभूत ढांचागत विकास और 15 स्कूलों में भवन निर्माण के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय व जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग का डीम्ड विश्वविद्यालय, 10 नए सरकारी कॉलेज व 12 कन्या कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा 4 नए पॉलीटेक्निक व 4 आइटीआई कॉलेज खोले जाएंगे।

बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण

बजट में 430 करोड़ रुपए का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए किया गया है। महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने और उनकी काउंसलिंग करने के लिए जयपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिलाओं को निःशुल्क दवा योजना में मुफ्त सैनेटरी नैपकिन देने की घोषणा की गई है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने के लिए राजीविका के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से निर्मित सामग्री की एक लाख रुपए तक की सीधी खरीद का प्रावधान अमृता सोसायटी की तर्ज पर होगा। शहीदों की वीरांगनाओं और अविवाहित शहीद के माता पिता का सम्मान भत्ता 5 हजार रुपए प्रति माह और एफडी राशि 5 लाख रुपए की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बालक-बालिकाओं को प्री-प्राईमरी शिक्षण व्यवस्था के साथ-साथ कुपोषण दूर करने के लिए पोषाहार दिया जाएगा। बजट में नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर में समेकित बाल पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की भी घोषणा की गई है। अनाथ बच्चों के संरक्षण व पुनर्वास के लिए गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर संचालित होगा।

युवाओं को सम्बलः उम्मीदों को लगे पंख

बजट में बेरोजगारी भत्ते में एक हजार रुपए की बढ़ोतरी और सरकारी विभागों में 50 हजार नई भर्तियों की घोषणा से बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों को पंख लगे हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को बेहतर बनाने और बेरोजगार युवाओं को तीन माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन की इंटर्नशिप कराए जाने और समान पात्रता वाली परीक्षाओं के लिए समान परीक्षा योजना लागू करने की घोषणा राहत प्रदान करने वाली साबित हो सकती है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए बजट में 1015 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने दस्तावेज व पुलिस प्रमाणीकरण के लिए वन टाइम पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की घोषणा भी बेरोजगारों को राहत देगी। बजट में संविदाकर्मियों के लिए सेवा नियम बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके लिए विभागवार अब अलग कैडर बनेगा। इससे प्रदेश के अलग-अलग विभागों में काम कर रहे दो लाख से अधिक संविदाकर्मी लाभान्वित हो सकेंगे। प्रदेश में 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। ये युवा मित्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का काम करेंगे।

बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस

राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इस बार बजट में 42071 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। घर-घर पानी पहुंचाने के साथ 12 अन्य नई पेयजल परियोजनाओं पर 6410 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 18 बांधों का जीर्णोद्धार होगा। नई ऊर्जा नीति, कृषि विद्युत वितरण कंपनी के गठन के अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।

बजट में 18943 करोड़ 23 लाख रुपए का प्रावधान बिजली तंत्र के सुधार के लिए प्रस्तावित है। आवास विकास के लिए भी बजट में 8776 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। गांवों और शहरों में सड़कों का विकास नई सड़क नीति के तहत किया जाएगा। अब तक डामर की सड़कों से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों से जोड़ा जाएगा।

पीडब्ल्यूडी इस पर काम शुरू करेगा। प्रदेश के 27 राजमार्गों पर 3880 करोड़ रुपए से विकास कार्य शुरू होंगे। छह हजार ग्राम पंचायतों में से कई पंचायतों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने, शहरी व ग्रामीण विकास में सड़क, ड्रेनेज, शौचालय आदि के मरम्मत के कामों को भी बजट का हिस्सा बनाया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि एक मई से प्रशासन गांव के संग तथा दो अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास दिलाया है कि सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है।

औद्योगिक ढांचा विकसित करेगी सरकार

कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, छोटे और मंझोले उद्योगों और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र को उबारने के लिए सरकार ने सीधे वित्तीय राहत का पिटारा खोला है। इससे घाटे में डूबे कामगारों को राहत मिलेगी। उद्योग विभाग के लिए बजट में 315 करोड़ 26 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। दस्तकारों-बुनकरों को ऋण-ब्याज माफी की सौगात भी दी गई है। बजट में सूक्ष्म, छोटे और मंझोले दर्जे के उद्योगों के लिए नई एमएसएमई नीति लाने की घोषणा भी की गई है। राज्य सरकार द्वारा नए वित्तीय वर्ष में 64 नए आद्यौगिक क्षेत्र प्रदेशभर में विकसित किए जाएंगे।

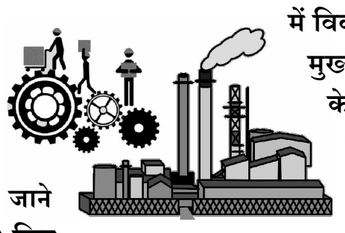

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार ग्रामीण युवाओं को रूरल आई स्टार्ट-अप का लाभ मिलेगा।

सरकार इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर लागू करेगी। ताकि ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को सामने लाया जा सके। उनमें नवाचार की इच्छा पनपे। इसके तहत जो युवा खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें आसानी से पांच लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र के दस्तकारों के तीन लाख रुपए तक के ऋण पर पूरी ब्याज राशि सरकार वहन करेगी। एक अन्य बड़ी घोषणा में सरकार ने बुनकर, दस्तकार, कुटीर और लघु श्रेणी के उद्योगों पर वर्ष 2000 तक बकाया वे सभी ऋण माफ कर दिए हैं, जो उद्योग विभाग ने विभिन्न योजनाओं में दिए थे। इससे करीब तीन हजार छोटे उद्यमियों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर